प्रकाशनार्थ

पटना, 2 सितंबर 2026। बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारी आज शाम होटल चाणक्य, पटना में एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री) द्वारा आयोजित 'गवर्नमेंट एनालिटिक्स एंड रिफॉर्म्स' विषयक दो-दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में विभागीय टीमों के साथ शामिल हुए। उद्घाटन एवं दीप प्रज्वलन के बाद सरकारी अधिकारियों की एक पैनल चर्चा हुई, जिसमें **सुश्री हरजोत कौर बम्हराह,** (**भा.प्र.से.)** अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व बोर्ड, बिहार, और **श्री कुमार रवि**, **(भा.प्र.से.)** सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार शामिल थे। **श्री स्पर्श गुप्ता, (भा.प्र.से.)** राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के एईडी ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। जिला एवं विभागीय प्रशासन के अपने अनुभव के आधार पर पैनलिस्टों ने टीमों की प्रारंभिक सोच पर प्रतिक्रिया दी और उन्हें अपनी नब्बे-दिन वाले योजनाओं में सबसे अधिक महत्व की समस्याओं को चुनने के लिए मार्गदर्शन दिया। इसके बाद टीमों ने रात्रिभोज से पहले अपनी सोच प्रस्तुत की।

कार्यशाला के पहले दिन सात विभागों — वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, योजना एवं विकास, तथा श्रम संसाधन — के मध्य-स्तरीय अधिकारी विभागीय टीमों के रूप में आद्री में एकत्र हुए। प्रत्येक टीम से अपेक्षा है कि वह कार्यशाला से अपने विभाग के लिए एक ठोस नब्बे दिन का कार्य योजना लेकर लौटे।

यह कार्यशाला सामान्य प्रशिक्षण प्रारूप से हटकर आयोजित की गई। लंबे व्याख्यानों के बजाय प्रत्येक सत्र की शुरुआत एक संक्षिप्त वार्ता से हुई और फिर टेबल पर व्यावहारिक कार्य की ओर बढ़ी, जहाँ अधिकारियों ने अपने ही विभाग को एक प्रणाली के रूप में परखा — विभाग द्वारा पहले से उत्पन्न आंकड़ों और अपने ही कर्मचारियों के विचारों का उपयोग करते हुए यह किया गया। प्रत्येक टीम ने अपने विभाग द्वारा पिछले पाँच वर्षों में किए गए एक सुधार को प्रस्तुत किया, जिसका उपयोग उसने पूरे दिन एक जीवंत उदाहरण के रूप में किया।

आद्री में दिन भर के सत्रों में तीन विषयों को शामिल किया गया। ये विषय थे: विश्व बैंक की गवर्नमेंट एनालिटिक्स हैंडबुक के आधार पर विभाग को एक मापनीय प्रणाली के रूप में देखना; बिहार में लोक प्रबंधन पर आद्री –एलएसई अध्ययन के निष्कर्ष, साथ ही स्टाफ सर्वेक्षण किस प्रकार तैयार किए जाते हैं इस पर व्यावहारिक शिक्षा। इसके अलावा यह भी देखा गया कि 6 देशों में 100 से अधिक सुधार क्यों टिकते हैं या नहीं टिकते हैं। आद्री के सहायक प्राध्यापक **डॉ दीपक कुमार** और **डॉ अर्पण शर्मा** ने आद्री – एलएसई सर्वेक्षण के विभिन्न भाग प्रस्तुत किए और विभागीय टीमों को इसके निष्कर्षों से अवगत कराया। **सुश्री बंदना प्रेयशी, आईएएस**, संयुक्त सचिव, उर्वरक विभाग, भारत सरकार, 'रिफॉर्म एज प्रोसेस' सत्र में ऑनलाइन शामिल हुईं और उन्होंने सरकार के भीतर सुधार का नेतृत्व करने तथा उसे लागू करने के अपने अनुभव विभागीय टीमों के साथ साझा किए।

यह कार्यशाला बिहार में लोक प्रबंधन पर अपनी तरह के पहले अध्ययन पर आधारित है, जो आद्री और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस (एलएसई) द्वारा संयुक्त रूप से 2024–25 के दौरान किया गया। इस अध्ययन में राज्य के सभी 38 जिलों में प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य उपकेंद्रों, आंगनवाड़ी और मनरेगा से जुड़े 1,767 फ्रंटलाइन एवं पर्यवेक्षी कर्मचारियों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें लगभग 3,000 सुविधा केंद्रों का दौरा भी शामिल था। अध्ययन में एक प्रतिबद्ध कार्यबल पाया गया जिसमें नौकरी से संतुष्टि का उच्च स्तर था। साथ ही विश्वास, कार्य की पुनरावृत्ति और बुनियादी ढांचे में कमियों जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी सामने आईं।

"इस कार्यशाला को असाधारण बनाने वाली बात यह है कि अब बिहार के पास अपनी प्रशासनिक मशीनरी के बारे में ठोस प्रमाण हैं, जो उसके अपने कर्मचारियों से एकत्र किए गए हैं," आद्री –एलएसई अध्ययन के सह-लेखक और कार्यशाला के प्रशिक्षकों में से एक **डॉ मार्टिन हॉस** ने यह कहा: "सर्वेक्षण एक ऐसे कार्यबल को दर्शाता है जो प्रतिबद्ध है और अपने काम पर गर्व करता है। आज अधिकारियों ने जिस प्रश्न पर काम किया वह यह है कि इस प्रतिबद्धता को कैसे आगे बढ़ाया जाए — अपने कार्यालयों के वास्तविक संचालन को मापकर, और सुधार को एक बार के आदेश के बजाय एक नियमित आदत बनाकर।"

"तीन दशकों से आद्री यह अध्ययन करता रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था और सरकार किस प्रकार कार्य करती है; यह कार्यशाला उस शोध को सीधे उन अधिकारियों तक वापस लाकर अगला कदम उठाती है जो राज्य के कार्यक्रमों को धरातल पर चलाते हैं," आद्री की एसोसिएट प्रोफेसर एवं सदस्य सचिव तथा अध्ययन की सह-लेखिका **डॉ अश्मिता गुप्ता** ने कहा। "सफलता की कसौटी यह नहीं है कि प्रतिभागियों ने इन दो दिनों में क्या सुना, बल्कि यह है कि इसके बाद के नब्बे दिनों में प्रत्येक विभाग अलग तरीके से क्या करना शुरू करता है। सातों टीमें अपनी-अपनी योजना, अपने ही शब्दों में, अपने-अपने कार्यालय के लिए तैयार करेंगी।"

"बिहार ने विकास, सेवा वितरण और कल्याण के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, और ये लक्ष्य पूरे होंगे या नहीं यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि सरकारी कार्यालय प्रतिदिन कितनी अच्छी तरह से चलते हैं," आद्री के कार्यक्रम निदेशक **डा0 निरज प्रकाश** ने कहा: "यह कार्यशाला मध्य-स्तरीय अधिकारियों — जो नीति को कार्रवाई में बदलते हैं — को कार्य योजना बनाने, कर्मचारियों के प्रबंधन, आंकड़ों के उपयोग और समस्याओं को हल करने के व्यावहारिक उपकरण प्रदान करती है। हम विभागों के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं, जैसे-जैसे वे अपनी नब्बे दिन वाले योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे।"

पैनल से प्राप्त मार्गदर्शन उन नब्बे दिन वाले कार्य योजनाओं को आकार देगा जिन्हें टीमें कार्यशाला के अंतिम दिन यानि कल, 3 सितंबर को, आद्री में तैयार कर प्रस्तुत करेंगी।

यह पाठ्यक्रम इस क्षेत्र के चार प्रमुख स्रोतों पर आधारित है: विश्व बैंक की गवर्नमेंट एनालिटिक्स हैंडबुक (2023); बिहार में लोक प्रबंधन पर आद्री –एलएसई अध्ययन (2024–25); रिफॉर्म एज प्रोसेस: इम्प्लीमेंटिंग चेंज इन पब्लिक ब्यूरोक्रेसीज़ (कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 2026); और हार्वर्ड केनेडी स्कूल द्वारा विकसित प्रॉब्लम-ड्रिवन इटरेटिव एडाप्टेशन (पीडीआईए) दृष्टिकोण।

(अभिषेक प्रसाद)